KIDWAI): (a) As per the information furnished by the concerned authorities, the per capita availability of drinking (potable) water in the 4 metropolitan cities is as follows:-

Bombay—112.5 to 135 litres per capita per day.

Madras—73 litres per capita per day.

Calcutta—259 litres per capita per day.

Delhi—238.5 litres per capita per day.

(b) No target has been fixed by the Planning Commission in this regard.

(c) Does not arise.

Plan allocation for agricultural sector

*378. SHRI KAILASH PATI MISHRA:
SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether the plan allocation for the agricultural sector in the First Five Year Plan was 14.9 per cent out of the total for all the sectors and it came down to only 5.9 per cent in the Seventh Five Year Plan; and

(b) if so, the reasons for the declining priority of agricultural sector in the planned development of the country and its consequences?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI G.S. DHILLON): (a) and (b) The Public Sector outlay for agriculture rose from Rs. 238.44 crores in the First Five Year Plan (1951-56) to Rs. 10573.62 crores in the Seventh Five Year Plan (1985—90) showing, in absolute terms, a significant increase, when only the same types of agricultural activities (excluding community development|local development| land other rural development activities) are taken into account. sectors increased from Rs. 2377.67 crores in the First Five Year Plan to Rs. 180,000 crore in the Seventh Five Year Plan. Thus, the share of agriculture comes to 10 per cent in the First Five Year Plan (and not 14.9 per cent as indicated in the Question) and 5.9 per cent in the Seventh Five Year Plan, when the common activities are taken into account.

2. The Planning Commission makes the Plan allocations for different sectors keeping in view the national priorities as enunciated by the National Development Council as also the total resource availability. The pattern of resource allocation in the Seventh Five Year Plan is designed to ensure that the country would remain self-sufficient in food through all-round development of agriculture. Increased emphasis has also been placed on investment in certain other crucial sectors like irrigation, energy, rural development, special area programmes, etc., benefits from which would also flow to the agriculture sector. Development of infrastructural facilities is one of the major objectives of the Seventh Five Year Plan so that shortages in critical inputs could be taken care of for the scale of activities envisaged in the Plan for ensuring faster growth of both agriculture and industry.

उत्तर प्रदेश में मछली-पालन की योजनायें

*379. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उत्तर प्रदेश में मछली पालन की बिल्कुल नई परियोजनाओं पर विचार कर रही है; और यदि हां, तो इन परियोजनाओं की मोटे-मोटे रूपरेखा क्या है; और

(ख) इन परियोजनाओं पर कितना खर्च आने की संभावना है?

कृषि मंत्री (श्री जी० एस० ढिल्लों) : (क) भारत सरकार ने —

और पश्चिम बंगाल राज्यों में मछली-पालन के लिये कार्बनिक अपजल (मल-जल) के उपयोग के वास्ते केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत एक प्रायोगिक परियोजना के लिये प्रशासनिक अनुमोदन जारी कर दिया है। इस प्रायोगिक परियोजना में उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 5-5 हक्टयर जल क्षेत्र के जल-मल द्वारा सम्भारित दो-दो मछली फार्म स्थापित करने की बात शामिल है। इनके विशेष उद्देश्य इस प्रकार हैं--(1) गंगा नदी के आस-पास मछली पालन के लिये जल-मल का प्रयोग, (2) गंगा नदी के नजदीक जल से भरे गड्ढों को मत्स्य पालन वाले तालाबों में बदलकर उनका विकास और (3) जल-मल के प्रयोग से मत्स्य पालन शुरू करने के लिय बुनियादी ढांचे की आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था। पूरी तरह विकसित होने पर इस प्रायोगिक परियोजना से लगभग 3000 कि० ग्रा० मछली प्रति हेक्टयर प्रति वर्ष की पैदावार मिलने की आशा है। इसके अलावा यह परियोजना जल-मल उत्सर्जन के निपटान और मछली पालन के लिये इसके प्रयोग के वास्ते प्रभावी साधन होगी।

एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना "मछुआरों के लिये राष्ट्रीय कल्याण निधि का भी सातवीं पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वयन के लिये अनमोदन किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत तीन मात्स्यकी संपदाओं में 100 मकानों (40 मकान काथिरांव में, 35 मकान भोजपुर में और 25 मकान पिछोरिया में) का निर्माण किया जायेगा। इस योजना पर होने वाला खर्च भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा 50: 50 के आधार पर वहन किया जाएगा।

(ख) जल-मल के प्रयोग से चलाये जाने वाले मत्स्य फार्मों की प्रायोगिक परियोजना की कुल अनावर्ती पूंजीगत लागत 128 लाख रुपये है, अर्थात् 64 लाख रुपये उत्तर प्रदेश के लिये राज्य सरकारों को शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता अनुदान के रूप में होगी। लगभग 3.6 लाख रुपये प्रति वर्ष का आवर्ती खर्च संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जायेगा।

उत्तर प्रदेश में "राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण निधि" नामक योजना की कुल लागत पूरी सातवीं पंचवर्षीय योजना, के लिये 76.92 लाख रुपये होगी, जिसमें से भारत सरकार का हिस्सा 38.46 लाख रुपये होगा। वर्ष 1987-88 के लिये 100 मकानों के निर्माण पर कुल 10.80 लाख रुपये की लागत आयेगी, जिसमें से भारत सरकार का हिस्सा 5.40 लाख रुपये होगा और शेष भाग राज्य सरकार देगी।

Distribution of Sub-standard and spurious fertilizers by FCI in Gujarat

*380. SHRI CHIMANBHAI MEHTA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the sub-standard or spurious fertilisers distributed by the officers of the Food Corporation of India at Patan and Siddhpur towns of Mehsana district in Gujarat;

(b) if so, what are the details thereof including the action taken against the officers involved; and

(c) whether Government propose to compensate the affected farmers and if sa, what are the details thereof?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI G.S. DHILLON): (a) and (b) It has come to the notice of this Ministry that the competent authority under Fertiliser (Contro' Order has filed a court case a' four dealers including the loca of Food Corporation of Indi sana Session Court for a